डीएवी मैनेजमेंट कॉलेज: नियमित प्रिंसिपल ने कार्यभार संभाला, छात्रों व स्टाफ में खुशी की लहर

फ़रीदाबाद (म.मो.) मैनेजिंग कमेटी की चहेती प्रिंसिपल नीलम गुलाटी का पत्ता पूरी तरह से कट जाने के बाद 2 फरवरी को ही डीएवी कॉलेज बंठिंडा के प्रिंसिपल डा. संजीव शर्मा को यहां का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया। डा. शर्मा के आने से तमाम छात्रों व स्टाफ में इस कदर खुशी की लहर दौड़ गयी जैसे भूखे को रोटी और प्यासे को पानी मिल गया हो। अब तक प्रिंसिपल की कुर्सी पर काबिज रही नीलम दोपहर को घंटे दो घंटे के लिए आकर कुर्सी पर बैठ जाती थी और किसी को दिखती तक नहीं थी वहीं प्रिंसिपल शर्मा पौने नौ बजे ही कॉलेज गेट पर आ खड़े होते हैं। छात्र उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं और मन की बात करते हैं।

पिछले करीब आठ-नौ साल से खाली पड़ी प्रिंसिपल की कुर्सी पर प्रबंधन नीलम गुलाटी को ही लगातार एवं स्थायी तौर पर बैठाये रखना चाहता था जबकि वह प्रोफेसर तो क्या सहायक प्रोफेसर होने की शर्त भी पूरी नहीं करती थी। उसे फीस क्लर्क से जुगाड़बाजी के जरिये प्रोफेसर और फिर प्रिंसिपल बनाकर छात्रों एवं फैकल्टी पर थोप दिया गया था। प्रबंधन का यदि वश चलता और एआईसीटीई को थोड़ी शर्म न आती तो नीलम ही प्रिंसिपल पद से चिपकी रह जाती। कायदे से तो एआईसीटीई को ऐसी अयोग्य प्रिंसिपल को एक दिन भी इस पद पर नहीं रहने देना चाहिये था। परन्तु रिश्वतखोरी के दम पर एआईसीटीई को खामोश रखा गया।

जब पानी सिर के ऊपर से जाने की नौबत आ गयी, मामला कोर्ट कचहरी से होते हुए मीडिया में उछलने लगा तो एआईसीटीई ने प्रबंधन को अल्टीमेटम दिया कि वह छह माह में असली प्रिंसिपल की नियुक्ति करें वरना उनकी दुकान रूपी कॉलेज को ताला लगा दिया जायेगा। इस चेतावनी से हड़बड़ाई प्रबंधन कमेटी ने अखबारों में विज्ञापन देकर योग्य अभ्यर्थियों को इन्टव्यू के लिए आमन्त्रित किया। हड़बड़ाहट में दो बार गलत विज्ञापन भी दे दिये।

देखा जाये तो डीएवी इतनी बड़ी संस्था है कि उसके पास अपने एक से एक बढ़िया प्रिंसिपल मौजूद हैं। उनमें से किसी को भी तुरन्त यहां नियुक्त किया जा सकता था। परन्तु इनको तो चाहिए था नीलम गुलाटी। उसकी नियुक्ति के लिए एमडी युनिवर्सिटी में जुगाड़बाजी लगाकर उसे इन्टरव्यू में पास कराने में भरसक प्रयास किये। इन प्रयासों पर संस्थान का लाखों रुपया पानी की तरह बहा दिया गया। परन्तु सब बेकार गया जब खोटा सिक्का चल नहीं पाया। 31 जनवरी को इन्टरव्यू पैनल ने नीलम के दस्तावेज देखने के बाद उन्हें इन्टरव्यू करने के लायक नहीं पाया। मजे की बात तो यह रही कि इसके उपरांत किसी भी अभ्यर्थी का इन्टरव्यू नहीं हुआ और सब को भगा दिया गया। मतलब साफ था कि यह सारा ड्रामा तो नीलम को प्रिंसिपल बनाये रखने के लिए ही था और जब वह रिजैक्ट हो गयी तो इन्टरव्यू किस बात का? लेकिन एआईसीटीई की सख्त चेतावनी के चलते प्रिंसिपल की तुरन्त नियुक्ति भी जरूरी थी, इसलिये झट से डा. शर्मा का यहां का नियुक्ति आदेश दे दिया। डा. शर्मा प्रथम श्रेणी से एमकॉम व एमबीए तो पास हैं ही पीएचडी यानी डक्टरेट भी कर रखी है। इसलिये वे हर प्रकार से इस पद के योग्य हैं। देखा जाये तो पहली बार इस कॉलेज को कोई ढंग का प्रिंसिपल मिला है। अब देखना यह है कि प्रबंधन में बैठे शिकारियों को ये नये प्रिंसिपल साहब कब तक सुहाते हैं।

पीएम मोदी के ड्रामे और हकीकत.....

पेज एक का शेष

2014 में डिस्पेंसरियों की संख्या 1418 थी वहीं 2018 में बढ़कर 1500 यानी 5.78 प्रतिशत की वृद्धि। ईएसआई अस्पतालों की संख्या जो 2014 में 151 थी वह 2018 में बढ़कर 154 हो गयी यानी कुल 2 प्रतिशत की वृद्धि। समझा जा सकता है कि बीमाकृत मजदूरों की बढ़ती संख्या के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरे के समान बढ़ती डाक्टरों, डिस्पेंसरियों व अस्पतालों की संख्या के चलते इन मजदूरों को कैसी चिकित्सा सुविधा मोदी का यह ईएसआई कार्पोरेशन दे पा रहा होगा। अपने वेतन का साढ़े छह प्रतिशत लुटवाने के बावजूद मजदूरों को चिकित्सा के लिए जिस तरह भटकना पड़ता है उसके बाद मजदूर अपने को ठगा हुआ नहीं तो क्या समझेगा?

अपने अस्पतालों व डिस्पेंसरियों के साथ-साथ ईएसआईसी इलाज के लिए मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजने पर भी खर्च करती है। यह खर्च 2014 में 4859.90 करोड़ था जो 2018 में बढ़कर 6867.73 करोड़ यानी 41.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार ईएसआई मजदूरों को जो नकद सहायता पर खर्च करती है वह राशि 2014 में 598.69 करोड़ थी जो 2018 में बढ़कर 642.84 करोड़ यानी 7.37 प्रतिशत ही बढ़ी।

मजदूरों से वसूली ज्यादा और खर्चा कम करके ईएसआईसी के खजाने में 2014 में रकम अथवा मुनाफे का ढेर 36868.38 करोड़ था, वह 2018 में बढ़कर 74348.43 करोड़ यानी कि 101.66 प्रतिशत बढ़ गया। उक्त सभी आंकड़े 31 मार्च 2018 तक की बैलेंस रिपोर्ट, जो संसद में पेश की गयी है, से लिये गये हैं। ईएसआईसी की वेब साइट पर भी देखा जा सकता है। बीमाकृत मजदूरों की बढ़ती संख्या व ईएसआई कार्पोरशन द्वारा धन संग्रह की गति को देखते हुए पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि 31 मार्च 2019 की रिपोर्ट में कार्पोरेशन का धन संग्रह एक लाख करोड़ से भी ऊपर निकल जायेगा।

यही है मोदी की कर्मठता एवं तीव्र गति से काम करने का एक छोटा सा नमूना। अब खतरा यह है कि संघ व इससे जुड़े पूंजीपतियों की गिद्ध दृष्टि तो इस पर पड़ ही चुकी है। जानकार बताते हैं ईएसआई के इस खजाने से खेलने का अधिकार शीघ्र ही उन्हें मिलने वाला है।

सुधी पाठकों से अपील

31 वर्षों से 'मज़दूर मोर्चा' वैकल्पिक मीडिया के तौर पर अपने सुधी पाठकों को वह समाचार, विचार एवं जन उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता आ रहा है जिसे अन्य मीडिया छिपाने का प्रयास करता है। सुधी पाठक इतना तो समझ ही गये होंगे कि यह छोटा सा अखबार किसी भी राजनीतिक अथवा व्यवसायिक धड़े से जुड़ा नहीं है। जनहित में जो भी प्रकाशित करने लायक सामग्री हो पाती है उसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

बिना विज्ञापनों के, केवल पाठकों के सहयोग से चलने वाला यह छोटा सा अखबार आपको और अधिक बेहतर व निरंतर सेवा देता रहे इसके लिये आप से निवेदन है कि इसमें अपना आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। 'मज़दूर मोर्चा' नियमित रूप से खरीदकर पढ़ने वाले पाठक तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अखबार पढ़ने वाले पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे भी इसमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें। वार्षिक सहयोग के तौर पर 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये की धनराशि सामर्थ्य अनुसार 'मज़दूर मोर्चा' के निम्नलिखित खाते में डाले जा सकते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में

खाता संख्या : 451102010004150

IFSC CODE : UBIN0545112

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5
2. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
4. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
5. राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
6. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
7. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207

गतांक की चीर-फ़ाड़

भाजपा की बढ़ती हुई परेशानी

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मजदूर मोर्चा के 3-9 फ़रवरी के अंक में राजनीतिक, ऐतिहासिक, प्रशासनिक, सामाजिक, साहित्यिक आदि मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुए हैं। महात्मा गांधी शांति, समन्वय, अहिंसा तथा हिन्दू मुस्लिम एकता का प्रचार करते थे जो हिन्दुत्ववादियों को पसंद नहीं था। बीडी सावरकर अपने जीवन के पहले दौर में क्रांतिकारी थे और हिन्दू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे लेकिन उन्होंने बाकायद अंग्रेजों से माफी मांगकर अंडमान की सेल्युलकर जेल से रिहाई हासिल करने के बाद अंग्रेजों की नीति के अनुसार हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच वैमनस्य फैलाना अपना लक्ष्य बना लिया था। उन्होंने 'हिन्दुत्व' नाम की पुस्तक लिखी तथा द्विराष्ट्रवादी सिद्धांत का प्रसार किया।

आरएसएस व हिन्दू महासभा से दीक्षित नाथूराम गोडसे ने सावरकर की योजना के अनुसार 30 जनवरी, 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी। संघ परिवार ने इस हत्या को जायज ठहराते हुए प्रचार किया कि गांधीजी आजादी के बाद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए अनशन कर रहे थे जिससे नाराज 'देशभक्त' गोडसे ने उनकी जान ले ली तथा गोली मारने से पहले गोडसे ने गांधीजी को चरण स्पर्श किये जिससे प्रकट था कि वह गांधीजी की इज्जत करते थे।''हिन्दुत्व ने की 'महानतम हिन्दू' गांधी की हत्या 'से संघ परिवार के इन दावों व झूठे प्रचार का पर्दाफाश हो जाता है। गांधीजी को मारने की पहले भी जून 1934, मई 1944, सितम्बर 1944 व 20 जनवरी 1948 में बार-बार कोशिश हुई थी जिनमें से अंतिम तीन बार गोडसे ने ही असफल प्रयास किये थे। स्पष्ट है कि गांधीजी हिन्दुत्व की विचारधारा के शिकार बने।

गौरतलब है कि गांधीजी की पुण्य तिथि पर अलीगढ़ में अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के नेताओं का एक वीडियो 'हे राम! बापू को मारने का फोटो सेशन।' सामने आया, जिसमें मीडिया कर्मियों के सामने हिन्दू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव पूजा शकुन पांडेय ने गांधीजी के पुतले में नकली पिस्टल से गोलियां मारी। इस महिला पदाधिकारी के संघ परिवार व भारतीय जनता पार्टी ;भाजपाद्ध के शीर्ष नेताओं से गहन संबंध है। आश्चर्य है कि संघ परिवार, मोदी सरकार तथा उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की। इस प्रकरण से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि हिन्दुत्सवादियों की मानसिकता में अब भी गांधीजी के प्रति जहर भरा हुआ है।

आजादी की लड़ाई के दौरान आरएसएस से संबंधित किसी भी व्यक्ति या कार्यकर्ता ने अंग्रेजों के विरूद्ध किसी भी आंदोलन अथवा गतिविधि में भाग नहीं लिया और ना ही कभी तिरंगे झंडे को सैल्यूट किया, बल्कि आरएसएस ने हमेशा भगवे झंडे को महत्व दिया। तत्कालीन अखबारों के अनुसार 30 जनवरी, 1948 को जब महात्मा गांधी की हत्या की गई तब आरएसएस के लोग तिरंगे झंडे को पैरों से रौंद रहे थे। इस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि राष्ट्रीय झंडे का अपमान करके अपने आपको देशद्रोही साबित कर रहे थे। इस पूरे प्रकरण का 'आरएसएस ने 1948 में तरंगे को पैरो तले रौंदा था' में बेबाक समीक्षा की गई है। विडम्बना है कि अब संघ परिवार व भाजपा राष्ट्रप्रेम की बातें कर रहे हैं तथा अपने विरोधियों को राष्ट्रदोही कहने में जरा सी भी हिचक नहीं करते।

अमृतसर के गोल्डन टैम्पल में जरनैल सिंह भिंडरावाले के अलगाववादी खालिस्तानी आंदोलन के विरूद्ध ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिक्ख अंगरक्षकों द्वारा हत्या करने के फलस्वरूप हुए सिक्ख विरोधी नरसंहार के कारण भाजपा व मोदी सरकार सदैव कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती रही हैं। जबकि आरएसएस के चिंतक, विचारक एवम् नीति निर्देशक व जनसंघ के नेता तथा पूर्व सांसद नानाजी देशमुख ने ब्लूस्टार ऑपरेशन की जमकर तारीफ की थी और उसका विरोध करने वालों को राष्ट्रदोही के रूप में पेश किया था तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पूरा समर्थन दिया था। नानाजी देशमुख ने 8 नवम्बर 1984 को एक लेख लिखकर इन दंगों का समर्थन किया था। 'भारत रत्न पाने वाले नानाजी देशमुख ने ठहराया था सिक्खों के नरसंहार को जायज में नानाजी देशमुख द्वारा कही गई मुख्य बातों का खुलासा किया गया है। सिक्खों का नरसंहार के पक्ष में खड़े होने वाले नानाजी को मोदी सरकार द्वारा भारत रत्न देने से मोदी सरकार व भाजपा का असली चेहरा बेनकाब हो गया है।

'कोबरापोस्ट ने किया 31 हजार करोड़ के घोटाले का खुलासा, कहा बीजेपी को चंदे में मिले करोड़ों रूपए' में उजागर किया गया है कि डीएचएफएस ने 36 बैंकों से 98718 रु. करोड़ रूपए का कर्ज लेकर 84982 करोड़ रूपए वादी के रूप में अन्य को दे दिये। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 182 के अनुसार चंदा देने से पहले किसी भी कंपनी को लगातार तीन वित्तीय वर्ष में लाभ की स्थिति में होना जरूरी है। लेकिन डीएचएफएल की शैल कम्पनियों आर.के. डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, स्किस रियलटर्स प्राईवेट लिमिटेड तथा दर्शन डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड ने भाजपा को करोड़ों रुपए चंदे में दिए जबकि ये तीनों कंपनियां घाटे में चल रही थीं। भ्रष्टाचार व घोटालों पर अंकुश लगाने का दावा करने वाली मोदी सरकार क्या इस घोटाले की जांच करायेगी?

आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में बैंकिंग क्षेत्र की दिग्गज हस्ती के.वी. कामथ तथा अन्य को पूछताछ के लिए सीबीआई द्वारा नामजद करने पर केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली भड़क उठे और ब्लॉग लिखकर सीबीआई को ही निशाने पर ले लिया। 'चन्दा कोचर पर एफआईआर से सीबीआई पर क्यों भड़के जेटली? से स्पष्ट है कि सीबीआई की जांच रिलायंस के करीबी के.वी. कामथ, चंदा कोचर आदि तक पहुंचने से जेटली खफा हो गये। वास्तव में यह मामला केवल चंदा कोचर तक ही सीमित नहीं है, इसके तार ऊपर तक पहुंचने की संभावना है।

मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में भाजपा की पराजय और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसानों की नाराजगी काम करने के लिए बजट में छोटे व सीमांत किसानों को 6000 रुपए वार्षिक तीन किश्तों में देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी व सरकार के अन्य मंत्री इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए अपनी पीठ थपथपाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि किसान नेता व विपक्ष इस अपर्याप्त छोटी सी राशि देने के लिए आलोचना कर सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। 'योगेन्द्र यादव: बजट में किसानों के वोट का सौदा किया है मोदी सरकार ने' में मोदी सरकार की इस कवायद की असलियत की परतें उधेड़ी गई है। किसानों को प्रतिमाह 500 रुपए अथवा प्रतिदिन 17 रुपए देने की घोषणा की आलोचना करने वालों को प्रधानमंत्री मोदी स्वयं उनको अपमानित करते हुए कह रहे हैं कि दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बैठने वालों को देश के दुर्गम व दूर क्षेत्र के गरीब किसानों के लिए 6000 रूपए की अहमियत का पता नहीं है। सरकार का समर्थन करते हुए सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहाकार कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि 6000 रुपए किसान की वार्षिक आया का 16.6 प्रतिशत है। हिन्दुस्तान टाईम्स के एक विश्लेषण के अनुसार आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि 6000 रुपए की राशि किसान की वार्षिक आय का 6 प्रतिशत से भी कम होगी। इस योजना को लागू करने से पहले ही किसानों ने विरोध जताते हुए प्रधानमंत्री को 17 रुपए के चेक भेजकर पेंशन राशि को नाकाफी बताया।

फांसी पर चढ़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और अंग्रेजों की गोली का शिकार होने वाले चन्द्रशेखर आजाद की जयंतियां तो मनाई जाती है, लेकिन भगत सिंह के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव एसेंबली बम फोड़ते, पैम्पफलेट फैंकने तथा इंकलाब जिन्दाबाद के नोर लगाते हुए गिरफ्तारी देने वो बटुकेश्वर दत्त की जयंती पर किसी भी राजनीतिक दल अथक सामाजिक संस्था द्वारा कोई श्रद्धांजलि नहीं दी जाती। आश्चर्य है कि स्वतंत्र भारत में भी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री केवी सहाय के अलावा किसी भी सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। उन्हें जीवन भर अभाव का जीवन जीना पड़ा। जिसकी 'भारत में पटना की सड़कों पर बिस्कुट बेचा करते थे स्वतन्त्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त' में चर्चा की गई हैं।

प्रयागराज में कुंभ के आयोजन पर योगी सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अखाड़ों की सुख सुविधाओं पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं तथा हेलीकाप्टर द्वारा जुलूस पर फूल बरसाये जा रहे हैं लेकिन श्रद्धालुओं को नजर अंदाज किया जा रहा है जिसकी 'कुभ दिव्यता और भव्यता के पीछे का अंधेरा' में विवेचना की गई है। मीडिया भी आंकड़ों को तो अपनी रिपोर्ट में कवर कर रहा है, जबकि कल्पवासियों की दशा के प्रति बिल्कुल उदासीन है।

प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस की जनरल सैक्रेटरी व पूर्वी उत्तरप्रदेश की प्रभारी बनाने से भाजपा की बढ़ती हुई परेशानी पर 'हाऊ इस दी जोश सर? - मोदी का विकास का नारा फुस होने पर 'वाह विकास, पिछले पांच साल में कितने मॉडर्न हो गए हो? - ये फैशन नहीं है, फटेहाल हो गया हूं।' यूपी में योगी सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने की बजाए साधु संतों को पेंशन देने पर 'रोजगार की चिंता छोड़ो, बाबा बनो पैंशन लो.....।' तथा मोदीजी द्वारा मन की बात में झूठ बोलने और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितशाह द्वारा पाखंड करने पर 'जन की बात-झूठ मन की बात-पाखण्ड-साम्प्रदायिकता' कार्टूनों द्वारा मोदी सरकार व योगी सरकार पर उपयुक्त व्यंग्य किया गया है।